

वर्ष 2025 को 'सुधार वर्ष' के रूप में मनाने का नरिणय

प्रलमिस के लयि:

[एकीकृत थरिटर कमांड](#), [आर्टफिशियल इंटेलजेंस](#), [मशीन लरनगि](#), [हाइपरसोनकिस](#), [रोबोटकिस](#), [राष्ट्रीय सुरकषा रणनीति](#), [अगनपिथ योजना](#), [साइबर युद्ध](#), [सीडीएस](#), [भारत-यूएस आईसीईटी पहल](#) ।

मेन्स के लयि:

भारत के सशस्त्र बलों में सुधार की आवश्यकता है ।

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बहु-क्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्रम सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परसिथितियों से नपिटने के लयि तैयार बल में रूपांतरति करने हेतु वर्ष 2025 को 'सुधार वर्ष (Year of Reforms)' के रूप में मनाने का नरिणय लयि है ।

नोट:

भारतीय सेना वर्ष 2024 को 'टेक्नोलॉजी ऐक्सांरप्शन ईयर' के रूप में मना रही है ।

वर्ष 2025 को 'सुधार वर्ष' के रूप कौन-से क्षेत्र चनिहति कयि गए हैं?

- युक्तता एवं एकीकरण: सैन्य सेवाओं के बीच सहयोग को मज़बूत करना और [एकीकृत थरिटर कमांड \(ITC\)](#) की स्थापना को सुगम बनाना ।
 - अंतर-सेवा सहयोग एवं प्रशकषण के माध्यम से परचालन आवश्यकताओं और संयुक्त परचालन क्षमताओं की साझा समझ वकिसति करना ।
 - इनमें तरिवनंतपुरम स्थति समुद्री कमान, जयपुर स्थति पाकसितान-केंद्रति पश्चिमी कमान और लखनऊ स्थति चीन-केंद्रति उत्तरी कमान शामिल हैं ।
- उभरती हुई प्रौद्योगिकियों: सुधारों को [साइबर व अंतरकष](#) जैसे नए क्षेत्रों तथा [कृतरमि बुद्धमिता](#), [मशीन लरनगि](#), [हाइपरसोनकिस](#) और [रोबोटकिस](#) जैसे उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रति होना चाहयि ।
 - भवषिय के युद्धों को जीतने के लयि आवश्यक संबद्ध रणनीति, तकनीक और प्रकरयिाँ भी वकिसति की जानी चाहयि ।
 - रक्षा क्षेत्र और असैन्य उद्योगों के बीच [प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व ज्ञान साझाकरण](#) को सुवधाजनक बनाना तथा व्यापार को आसान बनाकर सार्वजनिक-नजी भागीदारी को बढ़ावा देना ।
- अधगिरहण को सरल बनाना: क्षमता वकिस में तेजी लाने और उसे मज़बूत बनाने के लयि अधगिरहण प्रकरयिाँ को सुव्यवस्थति और समयबद्ध कयि जाना चाहयि ।
- रक्षा नरियातक: भारत को रक्षा उत्पादों के एक वशिवसनीय नरियातक के रूप में स्थापति करना , भारतीय उद्योगों और वदिशी [मूल उपकरण नरिमाताओं](#) के बीच अनुसंधान एवं वकिस तथा साझेदारी को बढ़ावा देना ।
 - भारत का रक्षा नरियात वर्ष 2014 के 2,000 करोड रुपए से बढ़कर 21,000 करोड रुपए से अधिक हो गया ।
- वयोवृद्ध कल्याण और स्वदेशी संस्कृति: वयोवृद्धों की वशिषजता का लाभ उठाते हुए उनके कल्याण को सुनश्चिति करना ।
 - इसके अतरिकित, आधुनक सेनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाते हुए, [स्वदेशी क्षमताओं के माध्यम से वैश्वकि मानकों को प्राप्त करने में भारतीय संस्कृति](#) पर गर्व और आत्मवशिवास को बढ़ावा देना ।

भारत की डफेंस मलिटरी/रक्षा सेना की वर्तमान स्थति क्या है?

- आयातक से नरियातक: भारत सबसे बड़े शस्त्र आयातक से प्रमुख नरियातक बन गया है, वर्ष 2023-24 में रक्षा नरियात 210.83 बलियिन

- रुपए तक पहुँच गया है, जिसमें वर्ष 2028-29 तक 500 बिलियन रुपए का लक्ष्य रखा गया है।
- रक्षा अधिग्रहण में सुधार: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) घरेलू उद्योग को प्राथमिकता देती है, जिसके अंतर्गत भारतीय कंपनियों को प्रमुख प्रणालियों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने तथा रक्षा खरीद में स्वदेशी सामग्री (IC) को 50% या उससे अधिक तक बढ़ाने की आवश्यकता होती है।
- नज़्ज़ी क़्षेत्र की भागीदारी: वर्ष 2022-23 तक नज़्ज़ी कंपनियों भारत के रक्षा उत्पादन में 20% का योगदान देंगी।
 - वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स सैन्य विमानों के लिये भारत का पहला नज़्ज़ी क़्षेत्र का कारखाना है, जो C-295 परिवहन विमान को समर्पित है।
- रक्षा औद्योगिक विकास: भारत का रक्षा उत्पादन कारोबार वर्ष 2016-17 में 740.54 बिलियन रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,086.84 बिलियन रुपए हो गया, जिसमें वर्ष 2023 तक 14,000 MSME और 329 स्टार्टअप रक्षा क़्षेत्र में शामिल होंगे।

रक्षा बल में सुधार की आवश्यकता क्यों?

- राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) का अभाव: NSS का अभाव राजनीतिक इरादों और सैन्य अभियानों के बीच अंतर उत्पन्न करता है, जिससे राष्ट्रीय नीतियों के साथ रक्षा रणनीतियों का संरेखण कमज़ोर होता है।
 - इसके परिणामस्वरूप चीन और पाकिस्तान जैसे उभरते खतरों के प्रति तैयारी में कमी आई है।
- साइबर युद्ध का उदय: साइबरस्पेस युद्ध का पाँचवा क़्षेत्र है, जिसमें राज्य प्रायोजित अभिक्रिया और स्वयं राज्य प्रमुख आर्थिक मापदंडों और सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुँचाते हैं।
 - एस्टोनिया तथा अन्य संघर्षों में यह देखा गया, जिसमें नवीनतम उदाहरण यूक्रेन-रूस साइबर युद्ध है।
- आयात पर निर्भरता: भारत वर्ष 2019-23 की अवधि के लिये वशिव का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है, जिसमें वर्ष 2014-18 की अवधि की तुलना में आयात में 4.7% की वृद्धि हुई है।
 - स्वदेशीकरण की धीमी गति और प्रतिस्पर्द्धी घरेलू रक्षा उद्योग के निर्माण में चुनौतियाँ रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता में बाधा डालती हैं।
- संयुक्तता का सांस्कृतिक प्रतिरोध: भारतीय सेना के सेवा-वशिष्ट दृष्टिकोण, जिसमें प्रत्येक शाखा (सेना, नौसेना, वायु सेना) अपनी स्वायत्तता बनाए रखती है, के कारण एकीकृत मॉडल अपनाने में प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है।
- अपर्याप्त वित्तपोषण: नरिपेक्ष रूप से पर्याप्त आवंटन के बावजूद, यह वशिष्ट रूप से प्रौद्योगिकी, उपकरण और बुनियादी ढाँचे जैसे क़्षेत्रों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.9% है, जो रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सीमित करता है।
 - वर्ष 2020 में रक्षा क़्षेत्र में FDI की सीमा को स्वचालित मार्ग से 74% तक और आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच के लिये सरकारी मार्ग से 100% तक बढ़ा दिया गया।
- तदर्थ खरीद प्रक्रियाएँ: वर्ष 2020 में गलवान संघर्ष के बाद, सशस्त्र बलों को महत्त्वपूर्ण क्षमता अंतराल को दूर करने के लिये आपातकालीन खरीद के लिये वशिष्ट अधिकार दिये गए थे, जिससे सामरिक आवश्यकता के बावजूद रणनीतिक तत्परता की कमी उजागर हुई।
- अल्पकालिक नीति: अग्नपिथ योजना की आलोचना इसकी 6 महीने की छोटी प्रशिक्षण अवधि के लिये की गई है, जिससे वास्तविक युद्ध के लिये रंगरूटों की तत्परता के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
 - 4 वर्ष की सेवा अवधि में अनुभवी कार्मिकों को खोने का जोखिम रहता है, जिससे सेना की क्षमता और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

रक्षा बलों में सुधार के लिये भारत की पहल क्या हैं?

- रक्षा औद्योगिक गलियारे
- आयुध निर्माणी बोर्डों का नगिमीकरण
- डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज
- सृजन पोर्टल
- रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (iDEX)
- मशिन रक्षा ज्ञान शक्ति

अमेरिका में गोल्डवाटर-निकोलस सुधार

- परिचय: गोल्डवाटर-निकोलस रक्षा पुनर्गठन अधिनियम, 1986 ने सैन्य प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने के लिये अमेरिकी रक्षा विभाग का पुनर्गठन किया।
- ये सुधार वयितनाम युद्ध (1955-1975) और ऑपरेशन इंगल क्लॉ (ईरान में बंधकों को बचाने का असफल अमेरिकी मशिन) के बाद चनिहति गए मुद्दों को संबोधित करने के लिये तैयार किये गए थे।
- लक्ष्य: प्राथमिक लक्ष्य संयुक्त सैन्य अभियानों में सुधार करना, नागरिक नियंत्रण को मज़बूत करना और रक्षा नरिणय लेने को सुव्यवस्थित करना था।
- प्रमुख प्रावधान:
 - राष्ट्रपति को बेहतर सैन्य सलाह

- एकीकृत लड़ाकू कमांडरों के लिये स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ
- एकीकृत कमांडर के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ
- रणनीति निर्माण और आकस्मिक योजना
- संसाधनों का कुशल उपयोग
- संयुक्त अधिकारी प्रबंधन
- संयुक्त सैन्य अभियानों की प्रभावशीलता
- रक्षा प्रबंधन और प्रशासन

आगे की राह

- संस्थागत सुधार: **चीफ ऑफ डीफेंस स्टटाफ (CDS)** और **सैन्य मामलों के विभाग (DMA)** की स्थापना एक सकारात्मक कदम है लेकिन इनके बीच ज़िम्मेदारी वितरण को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
- CDS द्वारा सैन्य निर्णय लेने में नेतृत्व करने के साथ नागरिक-सैन्य अंतराल को कम करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- प्रौद्योगिकियों का एकीकरण: स्वायत्त प्रणालियाँ, साइबर युद्ध एवं AI पर ध्यान केंद्रित करने से भारत को चीन या पाकिस्तान के साथ संभावित संघर्षों में तकनीकी बढ़त मलि सकती है।
- खुफिया जानकारी, नगिरानी, टोही (ISR) एवं सटीक हमलों में ड्रोन क्षमताओं का वस्तितार करने से परचालन अनुकूलन में वृद्धि होगी।
- घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देना: घरेलू रक्षा क्षेत्र को मज़बूत करने के लिये सार्वजनिक-नजिी भागीदारी एवं वदिशी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिये।
- संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन को महत्त्व दिये जाने के साथ वषिम लाभ प्रदान करने वाली प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- रक्षा सहयोग को अधिकितम करना: भारत-अमेरिका iCET पहल जैसी क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्तियों के साथ रक्षा सहयोग का वस्तितार करने से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता तथा सुरक्षा को बढ़ावा मलि सकता है।
- राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (NDU): भारत को रणनीतिक विचारकों एवं योजनाकारों का एक मज़बूत केंडर वकिसित करने के क्रम में रक्षा रणनीतियों, नीतियों और प्रौद्योगिकियों में उन्नत प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु NDU की स्थापना को प्राथमिकता देनी चाहिये।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वर्ष 2025 के लिये भारतीय रक्षा बलों में प्रस्तावित सुधारों एवं संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला "टरमनिल हाई एल्टीट्यूड एरथिा डीफेंस (THAAD)" क्या है? (2018)

- एक इज़रायली रडार प्रणाली
- भारत का स्वदेशी मसिाइल रोधी कार्यक्रम
- एक अमेरिकी मसिाइल रोधी प्रणाली
- जापान और दक्षिण कोरथिा के मध्य एक रक्षा सहयोग

उत्तर:(c)

??????

प्रश्न:रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष वदिशी नविश (FDI) को अब उदार बनाया जाना तय है: इससे भारतीय रक्षा एवं अर्थव्यवस्था पर अलपावधितथा दीर्घावधिमें क्या प्रभाव पडने का अनुमान है? (2014)